भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3244
जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024 (25 अग्रहायण, 1946 (शक)) को दिया जाना है।

"ओआईडीएआर सेवाओं में कर चोरी"

†3244. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के जांच अंग डीजीजीआई ने सूचना के आदान-प्रदान और प्रवर्तन उपायों के लिए विदेशी सरकारों के साथ पारस्परिक व्यवस्था करने और ई-गेमिंग और ऑनलाइन शिक्षा जैसी ओआईडीएआर सेवाओं में कर अपवंचन को रोकने के लिए वेबसाइटों को ब्लॉक करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीजीजीआई ने ऑनलाइन कसीनो जैसी कंपनियों पर ध्यान दिया है जो जानबूझकर कर संबंधी अनुपालन से बच रही हैं; और

(घ) क्या ये कंपिनयां सहयोग नहीं कर रही हैं और इसलिए वैश्विक विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचना के आदान-प्रदान से किसी अपवंचन को रोकने में सहायता मिलेगी?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): जी नहीं। डीजीजीआई की विदेशी सरकारों के साथ कोई पारस्परिक व्यवस्था नहीं है। हालाँकि, अब तक ऑनलाइन मनी गेमिंग/सट्टेबाजी/जुआ से संबंधित 642 विदेशी इकाइयां जांच हेतु चिन्हित की गई हैं।

जांच के दौरान गैर-उत्तरदायी और असहयोगी पाई गई ऑनलाइन गेमिंग इकाइयों को आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 14ए(3) के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ("एमईआईटीवाई") को उनकी वेबसाइटों/यूआरएल को अवरुद्ध करने के लिए सूचित किया गया है।

******